

DATE: 10/10/2020

B.A.(H) PART-2ND

SUBJECT: POLITICAL SCIENCE

PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)

CH: 10 (GOVERNOR)

LECTURE NO. - 07

By,

OM KUMAR SINGH

ASSISTANT PROFESSOR

DEPTT. OF POL. SC.

D.B. COLLEGE, JAYNAGAR

LNMU, DARBHANGA

### राज्यपाल के सम्बंध में सिफारिशें

विभिन्न कारणों की वजह

से 'राज्यपाल पद' के सम्बंध में विवाद उत्पन्न होते रहे हैं, इसी आलोक में राज्यपाल की नियुक्ति तथा भूमिका के सन्दर्भ प्रशासनिक सुधार आयोग (1966), राजमन्त्र समिति (1969), भगवान सहयोग समिति (1970) सरकारिया आयोग (1983) ने अपनी-अपनी सिफारिशें दी हैं, जो इस प्रकार हैं -

(i) प्रशासनिक सुधार (1966) (अध्यक्ष-मोहरजी देसाई) की सिफारिशें -

(i) उस व्यक्ति को राज्यपाल बनाना चाहिए जिसने सार्वजनिक जीवन और प्रशासन के विषय में लम्बा अनुभव हो और हलीय पूर्वाग्रहों से ऊपर उठने की क्षमता में विश्वास हो। अपने कार्यकाल की समाप्ति पर वह होकरा राज्यपाल नियुक्त कि जाने के लिए योग्य नहीं होना चाहिए

(ii) राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व सम्बंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेना चाहिए।

(iii) राष्ट्रपति को बेजी जाने वाली रिपोर्ट बनाने के समय राज्यपाल को स्वविवेक और स्वनिर्णय के आधार पर काम करना चाहिए।

(IV) राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयकों को सुरक्षित रखने के विषय पर स्वनिर्णय का प्रयोग करना चाहिए।

(V) सेवा निवृत्त होने के बाद न्यायाधीशों को राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन न्यायाधीशों सेवा निवृत्त होने के बाद आर्जन्तक जीवन में प्रवेश कर गया है और विधायक बन गया है या निर्वाचित पद पर है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल बनाया जा सकता है।

(VI) राज्यपालों के द्वारा किस प्रकार स्वविवेक की शक्तियाँ का प्रयोग किया जाय, इस विषय में निर्देश - संकेतों को केन्द्र की स्वीकृति पर राष्ट्रपति के नाम से जारी किया जाना चाहिए। उन्हें संसद के दोनों सदनो के समक्ष रखा जाना चाहिए। अर्थात् राज्यपाल के स्वविवेक शक्ति को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

(VII) जब भी राज्यपाल के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि मंत्रिमंडल का विधानसभा में बहुमत नहीं रहा है, तो इसका अंतिम निर्णय उसे विधानसभा का सत्र बुलाकर मंत्रिमंडल के समर्थन को देखकर करना चाहिए।

(VIII) जब कोई मंत्रिमंडल केली बड़े नीति निर्माण सम्बंधी विषय पर सदन में पराजित हो जाता है और यदि मुख्यमंत्री सदन भंग करने की सलाह देता है, ताकि वह सतहाताओं से निर्णय ले सके, तो राज्यपाल को उसकी सलाह मान लेनी चाहिए। अन्य मामलों में वह स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है।

(ix) राज्यपाल को न केवल अनुच्छेद 167 के प्रावधान के अनुकूल चुनना प्राप्त करनी चाहिए, बल्कि अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों को प्रभावी तौर पर पूरा करने के लिए ऐसा करना चाहिए।

### राजमन्मार समिति की विफारिशें—

(i) राज्यपाल की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करके की जानी चाहिए तथा इसके लिए सर्वोच्च न्यायालयिक व्यवस्था यह हो सकती है कि राज्यपाल की नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए गठित एक उच्च शक्ति प्राप्त अंगठन की सलाह के आधार पर किया जाय।

(ii) एक बार राज्यपाल पद पर रह चुके व्यक्तियों को इसी पद पर दूसरे कार्यकाल अथवा संस्कार के अधीन किसी अन्य पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए।

(iii) राज्यपाल को अपने कार्यकाल में पहले तब तक नहीं इंश्या जाना चाहिए, जब तक उच्चतम न्यायालय द्वारा जाँच के बाद उसके द्वारा दुर्व्यवहार या उसकी अक्षमता न साबित हो जाय।

(iv) संविधान में विशेष प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए, जो राष्ट्रपति को राज्यपालों के लिए निर्देश देने का अधिकार प्रदान करे।

(v) संविधान में शामिल इस प्रावधान को तत्काल इंश्या दिया जाना चाहिए कि मंत्रिमंडल राज्यपाल के प्रसाह-पर्यन्त पद पर रहेगा।

(vi) राज्यपाल को राज्य विधानसभा में वक्ता प्राप्त होना के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहिए।

(vi) जहाँ राज्यपाल की विधानसभा में किलीस्क हल के स्पष्ट बहुमत के सम्बंध में समाधान न हो, वहाँ राज्यपाल की विधानसभा का आखिरी मुख्यमंत्री के चयन के लिए बुलाना चाहिए और आखिरी में चुने गए व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहिए।

(vii) यदि मुख्यमंत्री किली मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह राज्यपाल को देता है, तो उसे मुख्यमंत्री की सलाह मान लेनी चाहिए।

(ix) यदि राज्यपाल की यह प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बहुमत खो दिया है, तो राज्यपाल को तत्काल विधानसभा का आखिरी बुलाकर मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने का निर्देश देना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री बहुमत साबित करने में असफल रहता है, तो राज्यपाल को मुख्यमंत्री के पद से बर्खास्त कर देना चाहिए।

राज्यपाल के सम्बंध शेष अन्य समितियों की विफारिशें अपने Lect पर हैं।